



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट-<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाषनं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्सनं. - 0755-2462136

No: 514/SEIAA/2025

Date: 25/05/2025

प्रति,

Smt. Shyamkali Kol,
R/o PO Pachokhar, Piparhari, Banda,
Naraini, Uttar Pradesh 210129
E-mail - shyamkalikol88@gmail.com

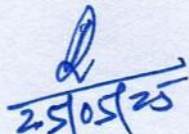
विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/458388/2024- Case No. P2/63/2024 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), for production capacity of 25,000 cum per annum, in an area of 4.610 ha., Khasra No. 396, Village- Jhari, Tehsil- Majhgawan , District Satna (M.P.) by Smt. Shyamkali Kol, R/o PO Pachokhar, Piparhari, Banda, Naraini, Uttar Pradesh 210129.

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 03.06.2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमति दी जाती है। तदनुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)


25/05/25
(श्रीमन् शुक्ला)

कार्यपालन संचालक, एण्डो
एवं सदस्य सचिव, SEIAA

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
 3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
 4. अध्यक्ष, SEIAA, एण्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
 5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
 6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
 7. कलेक्टर, जिला सतना (म.प्र.)।
 8. वन मंडलाधिकारी, जिला सतना (म.प्र.)।
 9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
 10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
 11. खनिज अधिकारी, जिला सतना (म.प्र.)।
 12. संबंधित फाईल।
- की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन संचालक, एण्को
एवं सदस्य सचिव, SEIAA

758 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 मई 2024

	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुगदरा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-20 दिनांक 21/08/12 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-70 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

3. Case No. P2/63/2024 Smt. SHYAMKALI KOL, OWNER, PO Pachokhar, Piparhari, Banda, Naraini, Uttar Pradesh 210129. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.610 ha. (25,000 cum per annum) (Khasra No. 396) Village- Jhari, Tehsil- Majhgawan , District Satna (M.P.). (MIN/458388/202 (B-2)

प्रस्तावित खदान समिति पूर्व 731वीं बैठक दिनांक 19/3/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-

- लीज क्षेत्र में कच्चे मकान एवं तालाब के संबंध में ग्राम पंचायत से का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
- संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करे।
- कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय प्रस्तुत करे।

उपरोक्त जानकारी परियोजन प्रस्तावक द्वारा जमा कर दी गई है जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 27/05/24 को परियोजना प्रस्तावक Smt. SHYAMKALI KOL online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इन्वायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि रीजनल प्रमुख भौमिकी एवं खनिकर्म से संशोधित माईनिंग प्लान पत्र दिनांक 04/04/2024 से अनुमोदित करा लिया गया है, जिसके माईनिंग प्लान के पृष्ठ क्रमांक-20 पर नॉन ब्लास्टिंग

758 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 27 मई 2024

का उल्लेख किया गया है। 20 मी. की दूरी पर चेक डेम होने की स्थिति में निर्धारित सेटबैक छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र 2.34 हे. एवं 2.27 हे. गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत का पत्र क्रमांक 21 दिनांक 06/05/2024 (अनुसार लीज एरिया में जो कच्चे मकान हैं वह खाली होने संबंधित पत्र) संलग्न किया गया है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन **25,000** घनमीटर/वर्ष
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना

S NO.	Particulars	Budget provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt.	0	1,23,600
	Cost for 300 days for 4.12 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 500/- per KLD		
2	Discharge of waste water 0.50 KLD @ 300 Working days /Capacity of Tanker (10 KLD) @ Rupees 2000 per tanker	0	30000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 130, Width 4.0m) @ 200Rs. /Meter	26000	2600
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	26000
<u>Plantation Scheme</u>			

758 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 मई 2024

A	1200 Nos. of sapling plants at the barrier zone (@ 30/per plant)	36,000	3990
B	130Nos. of saplings approach road @Rs 30/plant (including the cost of soil, manure and tree guard).	3900	
C	210 Nos. of saplings will be distributed to the nearby farmers @Rs 20/tree.	84200	0
D	Nos. of saplings will be plantation in community land @ Rs 50/-/ Saplings		

Labour Welfare			
5	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (14 x 12 feet) = 180 sq.ft	35,000	3,500
6	Portable toilets for Male & Female (1 for Each)	50,000	20,000
7	Occupational health Survey 14 labour @ 500 Rs./labour Rs./twice per year @500 x 2 x 14	Nil	16,000
8	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 14 labor @1200 Rs.	19,200	3000
9	First Aid Kit/Emergency Response Kit	3,000	3,000
10	Safety signage and warning boards like red flags, cones etc	60,000	3,000

Solid Waste Management			
11	Bins 2 Nos.	3,000	5000
12	Transport of Dry Waste/Wet Waste	2,000	
	Total E.M.P. Cost	3,22,300	1,16,090

CER

S.no..	CER Activities	Amount
---------------	-----------------------	---------------

758 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 मई 2024

1	अधोसंरचनाविकासकेलिएशासकीयहायडरसेकेंडरीस्कूल, झरीकेपालनशिक्षकसंघमेंअग्रलिखितधनराशिजमाकराईजाएगी।	60,000
	Total CER	60,000/-

Plantation

ग्रामJHARI मेंलगाएजानेवालेपेड़ोंकीकुलसंख्या2808 As per Updated Surface Area 2.34 Hec			
क्र.	प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतु नियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	मात्रा (संख्यामें)
1	Barrier zone	Neem, Peepal, Sesam, karanj, Khamer, Chirol etc.	350
2	Approach and Metalled road	Neem, Sesam, Arjun, Jamun, Mango etc.	130
3	Distribution in Farmers	Mango, Custard apple, Amrud, Jamun, Mulberry etc.	2328
	Total Number of Trees		2808

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No P2/37/2024 Shri SARSA SHARMA, 65-Sudama Nagar, Agar Road, Ujjain. Prior Environment Clearance for Shankarpur Stone Gitti Quarry in an area of 1.368 ha. (26066 cum per year) (Khasra No. 54/1, 54/2, 162/1P), Village-Shankarpur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान समिति पूर्व 725वी बैठक दिनांक 20/2/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लैस्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान के अंदर पश्चिम दिशा में कुछ मकान व शेड है, अतः

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.